



गत दिनों, 21 अप्रैल को, उत्तरी वियतनाम की डोंग मो लेक में स्थानीय लोगों को 93 किलोग्राम का शव तैरता हुआ दिखा। यह असल में यैंगसी जाट सॉफ्ट शैल टर्टल प्रजाति की आखिरी ज्ञात मादा का शव था, जिसे वियतनाम का "टर्टल गॉड" कहते थे। एशियन टर्टल प्रोग्राम (ए.टी.पी.) ने इसकी मौत पर लिखा, "हम बेहद आहत हैं, हमने इस टर्टल व इसके आवास को बचाने के लिए 17 साल तक कड़ी मेहनत की है।" इस मादा के मरने से अब सिर्फ दो यैंगसी सॉफ्ट शैल टर्टल बचे हैं और दोनों नर हैं। इनमें से एक तो पास की ही एक लेक, शुआन खान में है और दूसरा ईस्टर्न चाइना के सूजो शहर के जंतुआलय में। यह भी संभव है कि, डोंग मो लेक में एक और टर्टल हो, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। छोटे आकार के यैंगसी सॉफ्ट शैल टर्टल को "स्विनहोज सॉफ्ट शैल टर्टल" भी कहते हैं और इस समय केवल दो या तीन टर्टल सरवाइव कर रहे हैं इसलिए इन्हें विश्व का सर्वाधिक संकटग्रस्त जीव कह सकते हैं। ये कछुए मूलतः चीन की रेड रिवर के बेसिन, लोआंग यैंगसी रिवर तथा नॉर्दर्न वियतनाम में रहते थे। लेकिन नदियों पर बांध बनाने और वैंटलैड्स के सूखने से ये अपनी अधिकांश आवासीय रेंज से लुप्त हो गए हैं। हद से ज्यादा मछली पकड़ने, प्रदूषण तथा मीट व अण्डों के लिए इनके अत्यधिक शिकार के कारण भी इनकी आबादी बेहद कम हुई है। वियतनाम की पौराणिक कथाओं में इन कछुओं को "किम की" का प्रतीक माना जाता है। किम की वियतनामी कछुआ देवता हैं जिसने एक हजार साल के चीनी शासन को उखाड़ फेंकने में वियतनाम के लोगों की मदद की थी। आधुनिक हनोई शहर की होआम किम लेक वो स्थान है जहाँ कथित रूप से सम्राट एली लॉय ने कछुआ देवता "किम की" को जादुई तलवार लौटाई थी। सम्राट ने चीनियों को भगाने में इस तलवार का इस्तेमाल किया था। इस लेक में 2016 तक यैंगसी सॉफ्ट शैल टर्टल रहते थे। ए.टी.पी. के प्रमुख टिम मैककॉर्मिक ने 2019 में कहा था कि, संभव है यैंगसी जाट सॉफ्ट शैल टर्टल अभी वियतनाम व लाओस की झीलों में हों। इस प्रजाति का केवल एक जोड़ा भी इसको विलुप्ति से बाहर ला सकता है। एक मादा एक बार में 30 तक अण्डे दे सकती है और एक साल में एक से ज्यादा बार अण्डे देती है। पर इसके लिए बचे हुए टर्टल को ढूंढना जरूरी है। मादा यैंगसी जाट सॉफ्ट शैल टर्टल का उपर दिया गया चित्र सन् 2020 में लिया गया था।

ममता बनर्जी "पटाखा फैक्टरी" में बम विस्फोट की जांच एन.आई.ए. को सौंपने को क्यों राजी हो गयीं?

यह आम धारणा है कि, तथाकथित "पटाखा फैक्टरी" में असल में बम बनाये जाते थे तथा गैर कानूनी फैक्टरी का मालिक तृणमूल कांग्रेस का नेता तथा पंचायत का मुखिया है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। इस समय पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का समय अच्छा नहीं चल रहा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य

क्या आपको कम सुनाई देता है?
कान की मशीनें स्पीच थेरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaidhali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingofsolutions.com

■ मालिक "विस्फोट" के बाद उड़ीसा भाग गया, कुछ समय तक गिरफ्तारी टालने के लिये।

■ क्षेत्र में इस विस्फोट की घटना से काफी रोष है, क्योंकि मृतकों व घायलों की संख्या काफी अधिक है।

■ तृणमूल पार्टी की टीम, जो गांव को "विजित" करने जा रही थी, उसे गांव में प्रवेश नहीं करने दिया।

■ इस वातावरण को ठण्डा करने के लिये ममता बनर्जी ने विस्फोट काण्ड की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी एन.आई.ए. को सौंपने का निर्णय लिया।

सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत फिल्म "केरल स्टोरी" पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने सरकार को इस दलील को अमान्य कर दिया कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य की कानून व्यवस्था को स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह मात्र एक हठधर्मिता थी कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य के मुसलमान उग्र हो जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखना राज्य सरकार का कर्तव्य एवं दायित्व है। विपक्ष का मानना है कि अन्य किसी

कारण से न सही, केवल अपने कथन एवं अंदेशों को उज्वल ठहराने तथा प्रमाणित करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ दल स्वयं ही विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकता है तथा उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रमाणित कर सकता है।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान परेशानी का एक छोटा सा अंश मात्र है। पिछले दो दिनों में, बंगाल की राजनीति की स्थिति बड़ी खराब स्थिति में रही है तथा पटाखा बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री में हुये बहुत बड़े विस्फोट की घटना से सरकार बुरी तरह झुलसी हुई है। यह विस्फोट इतना ताकतवर था कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि यह पटाखा बनाने के सामान में हुआ है। यह एक सामान्य ज्ञान एवं (शेष पृष्ठ 5 पर)

ग्रैनाईट की खदान में दबने से श्रमिक की मौत

मालपुरा, 18 मई (निर्स)। लाम्बाहरिसिंह थाना क्षेत्र के रूपाहेली गांव के पास संचालित ग्रैनाईट की खदान में पत्थर की चट्टान गिरने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची लाम्बाहरिसिंह थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में

■ बताया जाता है, श्रमिक चट्टान के नीचे दब गया था। अब मृतक के परिजन 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।

रखवाया है। थानाधिकारी भागीरथ सिंह ने बताया कि, रूपाहेली के पास संचालित, धरती जतन ग्रैनाईट की खदान में चट्टान के नीचे एक श्रमिक दबने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जे.सी.बी. की सहायता से चट्टान को हटाकर शव को कब्जे में लिया और मालपुरा (शेष पृष्ठ 5 पर)

■ अनाद्रमुक इस घटनाक्रम से आल्हादित है तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव बना रही है, प्रदेशाध्यक्ष पर लगाया जाये।

■ दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष अनामलाई ने द्रमुक के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगाये थे और जवाब में द्रमुक ने भी काफी शोर मचाया था कि, कर्नाटक चुनाव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भारी रकम ले जाते हुए पकड़े गये, हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को जांच के बाद मिथ्या बताया था। पर, अब द्रमुक चाहती है कि, कर्नाटक की राज्य सरकार इस आरोप की नये सिरे से जांच करे।

■ तमिलनाडु से 39 सांसद निर्वाचित होते हैं, अतः यह राज्य लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा के लिये भारी महत्त्व रखता है, विशेषकर इसलिये भी, क्योंकि संभावना है कि, संसदीय चुनाव में उत्तर भारत में भाजपा कुछ सीटें खो सकती है।

■ भाजपा की इस मजबूरी का भी द्रविड़ पार्टियाँ आनंद ले रही हैं।

छवि परिवर्तन कार्यक्रम के तहत रिजिजू को विधि मंत्रालय से हटाया गया

प्र.मंत्री इस मंत्रिमण्डलीय परिवर्तन से यह "मैसेज" देना चाहते हैं कि, सरकार "जुडिशियरी" (सुप्रीम कोर्ट) से संबंध सुधारना चाहती है, जो पिछले दिनों काफी तनावपूर्ण हो गये थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। देश की न्यायपालिका के साथ अपनी सरकार के संबंध बेहतर बनाने तथा सरकार की छवि सुधारने की समझौते-सोची कोशिश के अंतर्गत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज न केवल विधि मंत्री किरन रिजिजू को हटा दिया, बल्कि विधि राज्य मंत्री एस.पी. बघेल को भी शिफ्ट कर दिया।

जहाँ रिजिजू अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण "अर्थ साईसेज" मंत्रालय में भेज दिये गये हैं, वहीं बघेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भेज दिया गया है। ज्ञातव्य है कि रिजिजू को विधि मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रोन्नत किये अभी एक साल भी नहीं हुआ था।

अभी हाल ही हुये कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हुई जबरदस्त पराजय के बाद भाजपा ने यह चकित कर देने वाली कार्यवाही की है, जो भी आम चुनावों से ठीक एक साल पहले। प्रधानमंत्री मोदी मृदुभाषी अनुसूच्य मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय में ले आये हैं ताकि न्यायपालिका के साथ

■ पहली बार विधि मंत्रालय का कार्यभार एक राज्य मंत्री (स्वतंत्र चार्ज) को दिया गया है। यह भी संकेत है कि, सरकार अपनी विधि संबंधी नीतियों में संशोधन करने की इच्छुक है।

■ निवर्तमान विधि मंत्री रिजिजू की लगातार सुप्रीम कोर्ट से रस्सा कशी चलती रही है, कोलीजियम सिस्टम को लेकर।

■ सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने जजों की नियुक्ति व तबादलों में देरी किए जाने पर आपत्ति की थी, और प्रशासनिक व न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी।

■ निवर्तमान राज्य विधि मंत्री को हटाने के लिये भी यह तर्क दिया गया है कि, जब विधि मंत्री स्वयं राज्य मंत्री होता है तो, उप मंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

■ पर, सच है कि, निवर्तमान विधि राज्य मंत्री ने टिप्पणी की थी कि, बहुत कम मुसलमान उदारवादी होते हैं और, जो दिखते भी हैं, केवल उदारवाद का मुखौटा पहनते हैं।

■ यह टिप्पणी उस समय आयी, जब मोदी व भाजपा मुसलमानों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और प्र.मंत्री को नयी छवि में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है।

तनावपूर्ण संबंध सुधर सकें।

रिजिजू, जो सरकार अत्यधिक उच्च कोटि के मंत्रियों से एक तथा सरकार के संकट मोचक माने जाते थे, को प्रोन्नत कर कैबिनेट मंत्री के रूप में विधि मंत्रालय भेजे हुये अभी एक साल

भी पूरा नहीं हुआ था।

मेघवाल संसदीय मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री हैं, के पास अब विधि मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी रहेगा। अगर तथ्य परक बात करें तो हाल ही के इतिहास में यह ऐसा पहला अवसर

होगा, जब विधि मंत्री कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं होगा। यह तथ्य न्यायपालिका के लिये इस बात का एक गूढ़ संदेश भी है कि मोदी सरकार अब तक हुए नुकसान को भरपाई के लिये भी तैयार (शेष पृष्ठ 5 पर)

शिव कुमार अपनी शर्त पर उपमुख्यमंत्री पद संभालने को तैयार हुए

कर्नाटक मंत्रिमण्डल में अब केवल एक उपमुख्यमंत्री होगा, हालांकि खड़गे स्वयं, एक दलित को और मु.मंत्री बनवाना चाहते थे।

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार राज्य के एकमात्र उपमुख्यमंत्री के रूप में अंततः कर्नाटक सरकार में शामिल हो गए। जिसके मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते थे कि दो उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं जिनमें से एक दलित समुदाय का हो। लेकिन उन्होंने शिवकुमार एक ही उपमुख्यमंत्री की मांग स्वीकार कर ली।

कांग्रेस, महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने यहाँ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, खड़गे ने अपना निर्णय बताने के लिए उन्हें (वेणुगोपाल) अधिकृत किया है। उन्होंने कहा, संसद के चुनाव सम्पन्न होने तक शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी-रणदीपसिंह सुरजेवाला, जिन्होंने वेणुगोपाल के साथ ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया, ने कहा, पत्रकार नाराज हैं कि कांग्रेस ने निर्णय जल्दी क्यों नहीं लिया। सुरजेवाला ने कहा, यह मीडिया का

अधिकार है, "हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं। यही कांग्रेस है।" उन्होंने कहा कि, गुरुवार शाम को कांग्रेस विधायकों की एक औपचारिक बैठक बैंगलूरु में आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार देंगे। रविवार को मुख्यमंत्री की घोषणा होगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12.30 बजे होगा है। टाइम का यह अंतर इसलिए रखा गया है ताकि विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो पाएं।

बंगाल में "द केरल स्टोरी" से प्रतिबंध हटा

नई दिल्ली, 18 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के आठ मई के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई.

■ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, फिल्म में प्रतिबंध लगाने जैसा कोई मुद्दा नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खुद भी फिल्म देखकर इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया है।

चंद्रचूड़ और और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ राज्य सरकार के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस पर प्रतिबंध का पर्याप्त आधार (शेष पृष्ठ 5 पर)

द्रविड़ पार्टियाँ, द्रमुक व अन्नाद्रमुक काफी प्रसन्न हैं, भाजपा की कर्नाटक में हार से

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अनामलाई बार-बार गठबंधन साथी अन्नाद्रमुक को पिन चुभो रहे थे। पर, कर्नाटक के उन तमिल भाषी क्षेत्रों, जिनमें चुनाव की जिम्मेवारी प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी गयी थी, में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है

-लक्ष्मण बैंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे, जिसमें भाजपा को करारी हार मिली है, का त्वरित प्रभाव तमिलनाडु में विपक्षी दलों अन्नाद्रमुक और भाजपा पर देखा गया है। जहाँ दोनों दलों के बीच तनावपूर्ण ही सही किन्तु आवश्यक गठबंधन है। दोनों दलों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के. अनामलाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेहतर होगा पार्टी अकेले चुनाव लड़े, हालांकि दिल्ली में बैठा पार्टी नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं है। अन्नाद्रमुक ने भी तब करारा जवाब दिया था तथा

उन्हें राजनीति में नौसिखिया और बचकाना करार दिया था और फिर भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा, ताकि गठबंधन चलता रहे।

लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अन्नामलाई को जो क्षेत्र दिए थे, वहाँ भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेवारी अपनी योग्यता साबित करने के लिए दी थी और अब जब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे में अन्नाद्रमुक प्रसिद्धेदह ज्यादा दबाव डालेंगे। कर्नाटक की हार ने अन्नाद्रमुक पर दबाव डालने की भाजपा की क्षमता कम कर दी है। भाजपा, जो

■ अन्नाद्रमुक इस घटनाक्रम से आल्हादित है तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर दबाव बना रही है, प्रदेशाध्यक्ष पर लगाया जाये।

■ दूसरी ओर प्रदेशाध्यक्ष अनामलाई ने द्रमुक के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगाये थे और जवाब में द्रमुक ने भी काफी शोर मचाया था कि, कर्नाटक चुनाव में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भारी रकम ले जाते हुए पकड़े गये, हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को जांच के बाद मिथ्या बताया था। पर, अब द्रमुक चाहती है कि, कर्नाटक की राज्य सरकार इस आरोप की नये सिरे से जांच करे।

■ तमिलनाडु से 39 सांसद निर्वाचित होते हैं, अतः यह राज्य लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भाजपा के लिये भारी महत्त्व रखता है, विशेषकर इसलिये भी, क्योंकि संभावना है कि, संसदीय चुनाव में उत्तर भारत में भाजपा कुछ सीटें खो सकती है।

■ भाजपा की इस मजबूरी का भी द्रविड़ पार्टियाँ आनंद ले रही हैं।

कि अन्नाद्रमुक पर दबाव डाल रही थी कि अलग हुए गुटों को पार्टी में वापस लिया जाए, अब ऐसा नहीं कर पाएगी। अन्नाद्रमुक नेता खुश है कि तमिलनाडु से संबंधित दोनों भाजपा नेता अनामलाई और सी.टी. रवि, जो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और तमिलनाडु के प्रभारी हैं, कर्नाटक में बुरी तरह असफल रहे हैं। सी.टी. रवि तो खुद चिकमंगलूर से प्रत्याशी थे, पर हार गए। कोलार और मांड्या जिलों, जहाँ काफी तादाद में तमिल आबादी रहती है, में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ प्रचार का जिम्मा अन्नामलाई को दिया गया था।

अन्नामलाई कर्नाटक व तमिलनाडु (शेष पृष्ठ 5 पर)

जल्लीकट्टू व बैलगाड़ियों की रेस को स्वीकृति मिली

नई दिल्ली, 18 मई (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सांडों की रेस में करने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू से संबंधित कानून को न्याय संगत बताते हुए इससे संबंधित तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कानून की वैधता को गुरुवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति

■ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य द्वारा पारित कानून में जानवरों के प्रति क्रूरता का ध्यान रखा गया है।

अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की संविधान पीठ ने तमिलनाडु के साथ इस प्रकार के पारंपरिक खेल से संबंधित महाराष्ट्र और कर्नाटक के कानूनों में पर भी अपनी मुहर लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जल्लीकट्टू पिछले कुछ सदियों से राज्य में चल रहा है और राज्य (शेष पृष्ठ 5 पर)

विचार बिन्दु

पूरे यत्न से इतिहास की रक्षा करनी चाहिए, इतिहास और अपना प्राचीन गौरव नष्ट कर देने से विनाश निश्चित है। -महाभारत

सावधान! जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी संकट में।

जलवायु परिवर्तन का संकट किसी एक देश का नहीं है अपितु धरती के सभी देश इस संकट से ग्रसित हैं। यह ग्लोबल संकट है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ वह कर सकता है, देश के विकास व खुशहाली के लिये, करना चाहिये।

हमारी धरती संकट में है। कार्बन उत्सर्जन के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न, सुरक्षा, आजीविका, पानी, पर्यावरण, बीज, स्वास्थ्य और धरती पर विपरीत असर पड़ रहा है। कहीं तूफान हैं, तो कहीं सूखा है। कहीं भूकम्प हैं तो कहीं मानव व जानवर बीमारियों से झूझ रहे हैं। नई-नई बीमारियाँ फैल रही हैं। नदियाँ सूख रही हैं। पहाड़ पिघल रहे हैं, पानी का पानी जहर बनने का रहा है। मौसम बदल रहे हैं। तूफान और बाढ़ से बस्तियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, समुद्र अपनी सीमा लांघ चुका है। अनाज की पैदावार कम हो गई है, धरती बंजर बनती जा रही है। जून 1992, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) हुआ जहाँ तापमान 1.5 डिग्री से. से अधिक बढ़ने से सभी 122 देश चिंतित थे। जबकी यह जानकारी दी गई कि 1.5 डिग्री से. से 2 डिग्री से. तक या इससे अधिक तापमान बढ़ा तो स्थिति भयंकर हो सकती है। संसार के देशों के मध्य क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इससे भी सफलता नहीं मिली। पेरिस एग्रीमेन्ट ने जरूर कुछ आशाएँ जगाई हैं। किन्तु यह स्व-विवेक पर आधारित है। इसे लागू करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। भविष्य अंधकार में है। सन 1992 में जो मिटिंग हुई थी उसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) का नाम दिया गया है इसे Earth Summit (पृथ्वी सम्मेलन) भी कहते हैं। इस संबंध में जो सम्मेलन हुआ उसे संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप सम्मेलन नाम दिया। इस संबंध में होने वाले सम्मेलन को कॉप कहते हैं। इसका अर्थ है 'कॉन्फरेन्स ऑफ पीपल्स'।

मानव के अधिकारों की घोषणा से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। मानव के अधिकारों में मानव के गरिमा मय जीने के अधिकार को मजबूत आधार मिला। सतत विकास के लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का रियो (2012) का परिणाम दस्तावेज हमारी भविष्य का कल्पना है और सतत विकास के 17 लक्ष्य व 169 निर्देश निर्धारित किये गये हैं, वे हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके द्वारा मानववादी संस्कृति से आगे बढ़कर धरती माँ के अधिकारों पर अपनी सोच को विस्तार दिया है। मानव के अतिरिक्त अन्य भी प्राणी हैं जो मिलकर पृथ्वी को बनाते हैं। हमने तो नदियों को भी प्राणी माना है। हमने धरती का अविभक्तपूर्ण दोहन किया है जबकि सभी प्राणियों को समान अधिकार है। हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है, "सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणां पश्यन्तु मा कश्चिदुःख भाग्यभवेत्"। इसी मूल मंत्र से हमें धरती को बचाना है।

Earth Summit (पृथ्वी सम्मेलन) से अभी तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कोई उपाय हमने नहीं के बराबर किया है। हमारे पापों के कारण जैव विविधता को बचाने में हम सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैव विविधता में लगभग एक मिलियन प्रजातियाँ एजमे समाप्त (विलोपित) होने के कगार पर हैं। 22 अप्रैल, 2023 को मदर अर्थ डे (Mother Earth Day) मनाया है अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को है इस दिन हमें जैव विविधता को पुनः उसी स्थिति में लेकर आने का संकल्प लेना है।

वर्तमान में भारत में उत्तर व अन्य हिमालय रीजन में जो तूफान आये हैं, जो बरबादी हुई हैं, हिमालय पिघला है, धरती हिली है। मोका तूफान ने राजस्थान में भीषण गर्मी के दिनों को (मई माह में) भी सर्दी का अहसास कराया है। इन प्रकृति के ताण्डवों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन सच्ची घटना है।

विकसित देश 80 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिये उत्तरदायी हैं, इस स्वीकृत स्थिति है। अतः जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के वे ही जिम्मेदार हैं, किन्तु छोटे देश जिनका कोई कसूर नहीं है, वे यह जानकर हैरान हैं कि उन्हें किस पाप की सजा दी जा रही है।

क्योटो प्रोटोकॉल अथवा पेरिस एग्रीमेन्ट अथवा अन्य संधि में कहीं भी इस बात का उल्लेख अथवा प्रावधान नहीं है कि यदि कोई मेश्वर अन्तर्राष्ट्रीय एग्रीमेन्ट के प्रावधानों की अवज्ञा करता है तो उसके विरुद्ध कोर्ट की कार्यवाही का क्या प्रावधान है? क्योटो प्रोटोकॉल में प्रावधान है, केस आर्बिट्रेशन में जा सकता है, किन्तु आर्बिट्रेशन उसी समय प्रभावशील होगा जब आरोपी आर्बिट्रेशन को स्वीकार करे। इसका अर्थ है कानूनी कार्यवाही अथवा कोर्ट की कार्यवाही सम्भव नहीं है। एक छोटे से देश Vanuatu जो जलवायु परिवर्तन से पीड़ित है ने इस संबंध में एक रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) यूएन असेम्बली में पारित कराया है कि इस बाबत International Court of Justice से कानूनी सलाह (Legal Opinion) ली जावे। इसके अतिरिक्त International Tribunal on Climate Change Dispute की स्थापना हो इस बाबत उचित कार्यवाही करे। साधारण रूप में हमारे देश में अनुच्छेद 21 और 1966 के सिविल कॉन्वेन्ट जैसा प्रावधान लगभग सभी देशों के संविधान में है। प्रदूषण के कारण कोई विवाद है तो वह मानव अधिकारों को प्रभावित करता है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिये हैं तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में जो सामाजिक व आर्थिक अधिकार माने जाते हैं वे सब मानव अधिकार ही हैं। मानव अधिकार डोमेस्टिक कोर्ट (Domestic Court) में प्रवर्तनशील है। यहाँ पर मानव अधिकार का उल्लंघन है, अतः एक देश अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्याय प्राप्त करने के लिये जा सकता है। यह भी रास्ता न्याय प्राप्त करने का हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस से अनुमति प्राप्त कर कोर्ट में कार्यवाही की जावे। सतत विकास के लक्ष्य में गोल-15 में जीवन व जमीन के अधिकार की बात का उल्लेख है, उसे अधिकार माना गया है। अर्थ डे, 22.04.2023 पर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गूटेरेस (Antonio Guterres) ने सब मेश्वर देशों को संदेश भेजकर निर्देश दिये हैं कि SDG kesâ 15Jesb Goal cesb Biodiversity Loss की बात है और इसे Biological Diversity से पानी, दवा, शेल्टर आदि के सन्दर्भ में जीवन को Sustain करने के हेतु आवश्यक माना है। जैव विविधता समाप्त होने की कगार पर है, 100 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि समाप्त हो रही है तथा 150 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि के नुकसान से फूड व पाने के पानी की सुरक्षा को खतरा है। इससे उक्त देश के निवासियों के अधिकार खण्डित हुये हैं।

भारत की सिविल सोसायटी सिकोयडिकोन, पैरवी व वियोण्ड कॉपनहेगन ने और अब मौसम ने कॉप की कोर्नर मिटिंग्स में सुझाव रखा था कि पेरिस एग्रीमेन्ट को सफल बनाना है तो उसे प्रवर्तनकारी बनाना होगा। भारत की उक्त सिविल सोसायटीज ने ब्रिटेन की सोसायटी से मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय टिब्यूनल की स्थापना के हेतु कुछ कदम उठाये थे। यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय टिब्यूनल की स्थापना की मांग के साथ, ऐसी पर्यावरण टिब्यूनल का विधान भी बनाया था और इस बात की सहमति हुई थी कि उसका कार्यालय भारत के मुम्बई शहर में होगा। भारत के पर्यावरण मंत्री स्व. अनिल माधव दवे को एक रिप्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया था, किन्तु उनके निधन के कारण यह बात आगे बढ़ नहीं सकी। पुनः इस ओर कदम उठाने का काम प्रारम्भ हो चुका है, जिसका उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण विशेषज्ञ सोमदत्ता के पत्र दिनांक 30.03.2023 से हुआ है। भारत की उक्त सिविल सोसायटीज को पुनः इस ओर कदम उठाना होगा और जो प्रस्ताव यूएन जनरल एसेम्बली में पारित हुआ उसे लागू कराने पर जोर देना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले देशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस से राय ली जावे कि दोषी देशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही है।

वर्तमान में भारत में उत्तर व अन्य हिमालय रीजन में जो तूफान आये हैं, जो बरबादी हुई हैं, हिमालय पिघला है, धरती हिली है। मोका तूफान ने राजस्थान में भीषण गर्मी के दिनों को (मई माह में) भी सर्दी का अहसास कराया है। इन प्रकृति के ताण्डवों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन सच्ची घटना है।

सावधान! पृथ्वी संकट में है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सांभर मे रोड लाइटें बंद होने से लोग परेशान

सांभरझील, (निसं)। यहाँ नया बस स्टैंड से कृषि उपज मंडी व पांच बत्ती चौराहा से न्यू मार्केट की तरफ जाने वाले रास्ते तक संपूर्ण रोड लाइटें विगत कई दिनों से देर तक चालू नहीं की जा रही है। शुक्रवार को भी देर शाम करीब 8 बजे तक रोड लाइटें चालू नहीं हो सकी थी। रोड लाइटें बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना

■ **पैसा बचाने के लिए सांभर पालिका ने रोड लाइटों में कटौती की**

पड़ रहा है।

पांच बत्ती चौराहा पर सौंदर्यकरण के नाम पर जिस खूबसूरत लाइट को करीब 50 हजार से अधिक खर्च कर लगावाया गया था। उसका भी कुछ सार्थक परिणाम निकल के सामने नहीं

आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पालिका की ओर से निगम की चल रही बकाया राशि का भुगतान का मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और रोड लाइटें देर तक बंद रखकर पालिका की ओर से आर्थिक बचत किए जाने की जुगाड़ की जा रही है, ताकि रोड लाइटों का बिल कम से कम आए जबकि इन रोड लाइटों का नियमानुसार पैसा आम जनता से नगरीय उपकरण में जोड़कर भी वसूला जाता है। लोगों का कहना है कि यदि पालिका प्रशासन रोड लाइटें और सफाई व्यवस्था पर ही पूरा खर्चखान नहीं कर पाती है तो फिर इस डिपार्टमेंट को सरकार को रखने का औचित्य ही क्या है। इस मामले में न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई विरोध कर रहे हैं और न ही लंबे समय से प्रशासन की ओर से कुछ समाधान किया जा रहा है।



सांभर पालिका क्षेत्र में कई जगहों पर रोड लाइटें बन्द रहने से आमजन को परेशानी हो रही है।

महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र लोग पहुंच रहे हैं

पावटा, (निसं)। मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविरों में अब सनाटा पसरने लग गया है। स्थिति यह है कि नाममात्र के लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे

■ **नगरपालिका का दावा है कि 9100 परिवारों में से 7400 ने करवाया पंजीकरण**

है। पावटा प्रगपुरा नगरपालिका का दावा है कि नगरपालिका क्षेत्र के 9100 परिवारों में से 7400 से अधिक परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका परिषद में स्थाई और वार्डों के तहत आदर्श रामलीला मैदान पावटा में एक अस्थायी मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का आयोजन 24 अप्रैल से नियमित जारी है। स्थिति यह है कि

गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे आदर्श रामलीला मैदान पावटा शिविर में लगाई गई अधिकांश कुर्सियाँ खाली रही।

उल्लेखनीय है कि शिविरों में भीड़ उमड़ने के कारण पूर्व में अतिरिक्त काउंटर लगाने पड़े थे। अस्थायी शिविर के कारण थोड़ी भीड़ कम हुई है। अस्थायी शिविर अन्य वार्डों में लगाने पर फिर से भीड़ आने लगेगी। वहीं शिविर में जोधपुरा निवासी चंद्रलाल, भैसलाणा निवासी कैलाश चंद, पावटा निवासी मोतीलाल, काशीराम लंबोरा सहित ग्रामीणों ने बताया कि शिविर में आते हैं लेकिन 11 बजे तक अधिकारी नहीं आते हैं। ई-मित्र संचालकों व कर्मचारियों के भरोसे शिविर चल रहे हैं। कई महिनों से पट्टों को लेकर चक्कर काट रहे हैं।



पावटा में महंगाई राहत शिविर में लोगों के नहीं पहुंचने से कुर्सियाँ खाली रही।

हड़ताल पर चल रही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

करौली, (निसं)। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।

तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जिले की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन दिनों हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को करौली कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।

उन्होंने मूल ग्रेड पे 3600, पदनाम परिवर्तन और पदोन्नति की मांग की इस दौरान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने और काम का बोझ बढ़ाने का भी आरोप लगाया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज्योति, रानी जादौन, सुनीता, आशा सैन, शायना, प्रभा कौशिक, ममता, प्रियंका, सपना सहित कई अन्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेतनमान बढ़ाने और श्रद्ध

■ **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा**

पे 3600 कि लंबे समय से मांग कर रही है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कम मानदेय पर काम कर रही हैं जिससे उन्हें आर्थिक तंगी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन करने और अन्य पदों पर पदोन्नति की मांग कर रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि है उनकी सरकार पर किसी प्रकार का आज भी धार नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांग पूरी करने की गुहार लगाई है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता गत 1 मई से लगातार हड़ताल पर चल रही है।



मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।

पार्क में मिलीं नशीले पदार्थों की खाली बोतलें

अनूपगढ़, (कासं)। क्षेत्र में अब नशा करने वाले लोग सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने लग गए हैं। गुरुवार अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 21 स्थित अंबेडकर पार्क में नशीले पदार्थों की खाली बोतलें मिलने पर वार्डवासियों ने रोष व्यक्त करते हुए इसकी सूचना पालिकाध्यक्ष प्रियंका बेलाण को दी। सूचना मिलने पर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बेलाण और पार्षद संजय अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर

■ **लोगों ने जताया आक्रोश पालिकाध्यक्ष को मौके पर बुलाया, पुलिस से कार्रवाई की मांग की**

पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड के लोग इकट्ठा हो गए। निरीक्षण के बाद पालिकाध्यक्ष ने मौके पर पुलिस बुलाई और नशे के खिलाफ

कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि इस पार्क में लगभग 6 वार्डों के लोग घूमने के लिए आते हैं। मगर आए दिन यहाँ नशेधुंध का जमावड़ा लगा रहता है। जिससे महिलाओं को पार्क में घूमने समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पालिकाध्यक्ष प्रियंका बेलाण ने बताया कि अंबेडकर पार्क में शराब और मेडिकेटेड नशे की खाली बोतलें मिली हैं और वार्डवासियों ने बताया कि

यहाँ नशे के खाली इंजेक्शन भी मिले हैं। पालिकाध्यक्ष बेलाण ने इसकी सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी। सूचना मिलने पर एसआई हंसराज और एसआई कालूराम मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने पालिकाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, महिलाओं और वार्ड वासियों पुलिस के समक्ष रोष प्रकट करते हुए नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसआई हंसराज ने बताया कि पुलिस

लगातार नशे की खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अंबेडकर पार्क में नशीले पदार्थों की खाली बोतलें मिलने पर जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों का आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाएगी और नशे के खिलाफ कार्रवाई की और भी तेज किया जाएगा।

राशिफल

शुक्रवार 19 मई, 2023

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2080, भरणी नक्षत्र प्रातः 7:29 तक, शोभन योग सांघ 6:16 तक, चतुष्पद करण प्रातः 9:33 तक, चन्द्रमा दिन 1:55 से वृष राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-कर्क, बुध-मेघ, गुरु-मेघ, शुक-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।



पंडित अनिल शर्मा

आज देव पितृकार्या अमावस्या, भालुका अमावस्या, बडपूजन अमावस्या, शनि जयन्ती, संत ज्ञानेश्वर जयन्ती है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:22 तक, लाभ-अमृत 7:22 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:04 तक, चर 5:25 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:05

■ **मेघ**
अपने अति आवश्यक कार्य को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

■ **तुला**
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

■ **वृष**
समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मित्रों/रिश्तेदारों से अनावन बढ़ने का भय बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

■ **वृश्चिक**
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

■ **मिथुन**
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

■ **धनु**
परिजनों के व्यवहार के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अस्व-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है।

■ **कर्क**
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

■ **मकर**
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में वाद-विवाद बढ़ने का भय बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

■ **सिंह**
शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात वर्तमान में चल रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

■ **कुंभ**
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। परिजनों के सहयोग से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है।

■ **कन्या**
संभावित धन प्राप्ति में विलम्ब होगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा।

■ **मीन**
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित खेत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा।

कलश का पूजन किया

भरतपुर (निस)। नवचेतना जागृति गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में होने वाले 108 कुंडिय नवचेतना जागृति महायज्ञ भरतपुर गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसी परिपेक्ष में भरतपुर जिले के वरिष्ठ गायत्री परिजनों द्वारा शांतिकुंज हरिद्वार जाकर यज्ञ की सफलता के लिए, सूक्ष्म में समाहित परम पूज्य गुरु देव पंडित रामशर्मा आचार्य व चंदनीय माता भगवती देवी के संरक्षण में बहिन शैलवाला पंड्या द्वारा शक्ति कलश भरतपुर गायत्री परिवार के परिजनों को दिया गया शक्ति कलश को हरिद्वार से भरतपुर आने पर रेलवे स्टेशन से भव्य शोभायात्रा के माध्यम से सभी गायत्री परिवार के परिजन व शक्ति स्वरूपा बहनों ने अपने सिर पर शक्ति कलश को धारण कर गायत्री शक्ति पीठ पर बैडबाजोंके साथ पहुंचाया। इस अवसर पर देवेन्द्र गुला चामड प्रमुख ट्रस्टी गायत्री परिवार द्वारा सप्लीक शक्ति कलश का पूजन किया गया तथा सभी से यज्ञ में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर नेतृत्व प्रभारी नरेन्द्र जोशी, डॉ जयसिंह कहलवाल, अनिल, वन, डॉ सुशील पाराशर आदि सैकड़ों गायत्री परिवार के परिजन उपस्थित थे।

भरतपुर (निस)। जिला कलेक्टर पर ग्रेड पे बढ़ाने एवं पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठी एएनएम एलएचबी कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने धरना स्थल पहुंचकर एएनएम एलएचबी की समस्याओं को सुना।

जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी ने कहा कि सरकार को एएनएम एलएचबी कार्मिकों की मांगों को मानना चाहिए। जिला कलेक्टर पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिनों से एएनएम एलएचबी धरना दे रही है।

राजस्थान एएनएम एलएचबी एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज कुन्तल ने बताया कि पिछले 18 दिनों से एएनएम एलएचबी कार्मिक अपनी जायज मांगों को लेकर भीषण गर्मी के बावजूद धरना पहरन कर रही है। लेकिन सरकार एएनएम एलएचबी की



भरतपुर में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर एएन.एम. कार्मिकों ने जिला अध्यक्ष सुमन चौधरी व सरोज कुन्तल (बाएं से पहली) के नेतृत्व में रैली निकाली।

मांगों पर कोई भी सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एएनएम एलएचबी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगी। एएनएम

एलएचबी के द्वारा भूख हड़ताल भी शुरू की जा सकती है। एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान की जिला अध्यक्ष सरोज कुन्तल ने बताया कि एएनएम

एलएचबी महिला कार्मिकों की मांग है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए।

समस्याओं को लेकर चर्चा

भरतपुर (निस)। जिला व्यापार महासंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिला महामंत्री नरेन्द्र गायल के नेतृत्व में जुगल किशोर सैनी के निज निवास पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग से मुलाकात की और व्यापारिक समस्याओं को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधि मण्डल में कोशाध्यक्ष जय प्रकाश बजाज, जिला प्रवक्ता विपुल घर्मा, प्रवीण जैन, अनिल हुड्डई, सतीष बजाज, सागर बजाज, जुगल किशोर सैनी इत्यादि व्यापारी थे।

जिला प्रवक्ता विपुल घर्मा ने बताया कि मंत्री सुभाष गर्ग से अनेक व्यापारिक समस्याओं को लेकर वार्ता हुई जिसमें मुख्य रूप से यू.डी. टैक्स व बिजली बिलों में स्थाई शुल्क व प्यूल सरचार्ज बढ़ाये जाने पर चर्चा हुई। यू.डी. टैक्स पर चर्चा कर व्यापारियों ने कुछ आपनी आपत्तित जताई जिस पर मंत्री महोदय ने धीरे धीरे संबंधित विभाग के अधिकारियों व मेयर के साथ संयुक्त मीटिंग कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।

बड़े हुए बिजली के बिलों के संबंध में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन मंत्री सुभाष गर्ग को सौंपा।

'विधायक के रूप में बाहरी व्यक्ति स्वीकार नहीं'

टोडाभीमा। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को सिंचाई के साथ-साथ पीने को पानी उपलब्ध कराने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जहां एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य फुटबॉल बनकर रह गई है तो वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के राजनेता महत्वकांक्षी जल योजना का सहारा लेकर विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचने का खाब सजो रहे हैं। वैसे तो क्षेत्र में कई नेता इआरसीपी के मुद्दे को चुनावी गणित में तब्दील करने का सपना सजो रहे हैं, परंतु इस कड़ी में अठाणी नाम भामाशाह के नाम से मशहूर हो चुके पंचायत समिति सदस्य रामनिवास मीणा का है जो इआरसीपी के नाम पर पैसे खर्च कर इआरसीपी का झंडा लेकर प्रदेश में दिसंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह बात भविष्य के गंभ में छुपी हुई है कि जनता की नब्ज क्या कह रही है। क्षेत्र के राजनीति के

जानकारों की माने तो टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र की जनता यह मन बना चुकी है चाहे विधायक भाजपा, कांटोस या निर्दलीय बने लेकिन क्षेत्र का विधायक विधानसभा क्षेत्र का निवासी ही क्षेत्र की जनता बाहरी व्यक्ति को विधायक के रूप में कतई स्वीकार नहीं करेगी। जबकि कुछ नेताओं के द्वारा इआरसीपी को आम जनता से ज्यादा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है जिस पर क्षेत्रीय राजनीतिक लोग अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने की जुगत लगा रहे हैं। मामला जनता से जुड़ा हुआ होने के कारण कांटोस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता इआरसीपी के मुद्दे पर खुलकर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। इआरसीपी के मुद्दे को बनाने के लिए पिछले 1 साल में दर्जनों सभाएं हुईं, महिला जागरूकता यात्रा निकली गई, पैसा पानी की तरह बहाया गया और भी बहुत कुछ हुआ लेकिन क्या वास्तव में पानी लाने का कोई इरादा है या फिर इआरसीपी से पानी नहीं विधायक निकलने का अदेश है। यह तय करना जनता का काम है।

मंदिर में पसरा सन्नाटा

करौली (नि.स.) कैलादेवी मंदिर में अंगराग चोला धारण के कारण मों. भक्तों को दर्शन बंद कर दिए हैं जिसके चलते मंदिर में गुरुवार को सन्नाटा पसरा रहा।

उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ तीर्थ स्थल कैलादेवी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 मई से 28 मई तक कैलादेवी का मंदिर में अंगराग चोला धारण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह 3 वर्ष में एक बार किया जाता है विद्वान पंडित प्रकाश चंद्र जती के सान्निध्य में 1 दर्जन से अधिक विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चारणों के बीच अंगराग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

गुरुवार को प्रातः 7:00 बजे कैलादेवी का आरती के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया और पट मंगल कर दिए गए।

उन्होंने बताया कि अब 28 मई दुर्गा अष्टमी को दोपहर फिर से मां0 भक्तों को राजराजेश्वरी कैला माता के दर्शन हो पाएंगे इस दौरान उन्होंने मां0 भक्तों से अपील की है कि 18 से 27 मई के बीच कैलादेवी नहीं आए क्योंकि भक्तों को माता रानी के दर्शन नहीं हो पाएंगे।

जनता के हाल जानने के लिए आशा मीना गांव-ढाणी पहुंची



भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशा मीणा ने गांव - ढाणी में ग्रामीणों की समस्याएं जानी।

सवाई माधोपुर, 18 मई। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशा मीणा गुरुवार को गांव - ढाणी में ग्रामीणों के दर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के हाल जानने के लिए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशा मीणा सुबह सूरवाल गांव पहुंची। आशा मीणा को अपने दर आया देख ग्रामीणों ने

उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया। इस बीच ग्रामीणों ने उन्हें गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कटौती से होने वाली परेशानी से अवगत करावते हुए पेयजल की समस्या से भी अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद मीणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से रात्रि के समय निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई करवाने व खराब पड़े पेयजल स्रोतों को ठीक

करवाने का आठह किया। जनहित से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए आशा मीणा के आठह पर संबंधित अधिकारियों ने उन्हें सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। सूरवाल के बाद आशा मीणा ने बड़ा गांव कहार, तारनपुर, श्रीपुरा, कितपुरा, मलारना चौड, बाडोलास एवं रावल पहुंचकर ग्रामीणों के हाल जाने।

सांसद ने केन्द्र सरकार कि योजनाओं का किया बखान

करौली। करौली-धौलपुर सांसद डॉ0 मनोज राजौरिया ने केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। साथ ही सांसद ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला।

करौली सफ्टिके हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिले सहित पूरे देश में जहां सड़कों का जाल बिछाया है। वहीं जिले में मेडिकल कॉलेज, चंचल पुल जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं दी है। देश के किसानों के लिए सम्मान निधि, गरीबों को उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाएं आमजन को राहत और विकास कार्य में मदद कर रही है। हर घर नल से जल योजना भी देश की आबादी को प्यास बुझाने का काम कर रही है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार है। राम मंदिर बनाने और

कश्मीर में धारा 370 को हटाने का काम भी केंद्र सरकार ने किया है। इस दौरान सांसद ने सीएम अशोक गहलोत पर प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बात कही। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि बिजली की दरों में बढ़े सरचार्ज ने उपभोक्ताओं के बिल में वृद्धि की है। सांसद ने महंगाई राहत कैम्प में आमजन को परेशान और भ्रमित करने का आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार सम्मान निधि का लाभ दे रही है।

इसी तरह राज्य सरकार चाहती तो आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे दे सकती थी। लेकिन राज्य सरकार चुनावी वर्ष में आमजन को झूठी राहत देने का दिखावा कर रही है। राहत कैम्प में आमजन परेशान हो रहा है। सांसद ने राहत कैम्पों को अपमान कैम्प का नाम दिया।

शनि जयन्ती की तैयारी

भुसावर (निस)। कस्बा भुसावर सहित ग्रामीण अंचल में शुक्रवार को कर्मफल दाता, सूर्यपुत्र और न्याय के कारक भगवान शनि देव का प्रकटोत्सव विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। जिसके लिए भक्तों ने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भुसावर के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित जन-जन की आस्था के प्रतीक कोटी वाले हनुमान जी मंदिर के पुजारी राधेन्द्र शर्मा जती ने जानकारी देते हुए बताया कि शनि जयन्ती इस बार 19, मई यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी, शनि जयन्ती ज्येष्ठ अमावस्या की कृष्ण पक्ष के दिन कर्मफल दाता, सूर्यपुत्र और न्याय के कारक भगवान शनि की जयन्ती श्रद्धा एवं उल्लास एवं धार्मिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। जती ने बताया कि शुक्रवार 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री का व्रत का त्यौहार भी मनाया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर में न्याय के देवता शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना, पंच तत्वों से शनिदेव की प्रतिमा का अभिषेक किया।

कलक्टर ने किया पदभार ग्रहण

भरतपुर (निस)। नव पदस्थापित 2015 बेंच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लोकबन्धु ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के पद का कार्यभार संभाल लिया है। एडीएम प्रशासन रतन कुमार ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबन्धु को पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्टर लोकबन्धु का बुके देकर स्वागत स्कार किया गया।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से भरतपुर की स्थितियों एवं विकास को लेकर चर्चा की। पदभार ग्रहण करने के पश्चात बंधु ने मीडियाकर्मीयों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग शिविरों के

माध्यम से स्थानीय लोगों को जनसमस्याओं का शत-प्रतिशत समाधान हो साथ ही उनका यह प्रयास रहेगा कि महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण कर योजनाओं का निर्धारित समय से प्रभावी लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्तरों पर की जा रही जनसुनवाईयों के माध्यम से अधिक से अधिक जनसमस्याओं का निस्तारण हो जिससे आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जिले की समस्याओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर नियमानुसार समाधान करने का प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) श्रीमती बीना महावर, नगर विकास न्यास के सचिव कमलराम मीणा, सहायक कलेक्टर सुश्री भारती भारद्वाज, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलक्टर ने समीक्षा बैठक की

भरतपुर (निस)। जिला कलेक्टर लोकबन्धु की अध्यक्षता में प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग शिविरों, महंगाई राहत कैम्पों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की गुरुवार को समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बजट घोषणाओं के तहत सम्बन्धित विभागीय अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों से प्रभावी समन्वय कर भूमि आवंटन के प्रकरणों को समय पर भिजवायें जिससे परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकें तथा आमजन को लाभ मिल सकें इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लें। उन्होंने शहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय नगर निकायों की साधारण सभा की बैठक पर प्रस्ताव लेकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अधिमान से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिविरों में कार्मिकों की ड्यूटी निर्धारित करें तथा राज्य सरकार के द्वारा शिविरों के लिए आवंटित

विभागीय कार्यों को शिविर में पूरा करायें साथ ही स्थानीय स्तर की समस्याओं का मौके पर मुआयना कर नियमानुसार निस्तारण करायें। उन्होंने डीओआरटी के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिये कि शिविरों में जनआधार के माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में होने वाले पंजीयन से वंचित परिवारों की सूची तैयार करें जिससे तहसील स्तर पर सूचियों के आधार पर पंजीकरण की प्रक्रिया को गति दी जा सके तथा राज्य स्तर पर जिले की रैटिंग में सुधार लाया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विभागीय डाटा के आधार पर वंचित उपभोक्ताओं का पंजीयन करारक लाभान्वित करायें। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये कि उचित मूल्य के दुकानदारों का सहयोग लेकर क्षेत्र के पात्र परिवारों को अनपूरणा एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत कर लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल करें तथा ऐसे महंगाई राहत शिविर जिनकी प्रगति कम है को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर गति लायें।

दीवार लेखन कार्य शुरू

भरतपुर (निस)। भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर प्रचार - प्रसार विभाग के द्वारा दीवार लेखन कार्य का प्रारंभ भरतपुर सारस चौराहे पर किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि राज्य सभा सांसद घनश्याम तिवारी रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल ने की। कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह विजवारी ने बताया कि दीवार लेखन का काम भरतपुर जिले के 1756 बुधों पर किया जाएगा।

एक बुध पर पांच स्थानों पर लेखन कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रवृत्ताचार, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, सहित तमाम मुद्दों को दीवार लेखन के जरिये जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। इस मौके पर प्रदेश मंत्री महेन्द्र सिंह जाटव, पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोली, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी, सतेन्द्र गायल, रविंद्र जैन प्रचार प्रसार जिला सह संयोजक उमेश पाराशर, दिनेश भातरा, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी गुप्ता जिला महामंत्री भगवानदास शर्मा जिला संयोजक अरविंद पाल सिंह, जिला प्रवक्ता नरेश सेन, हरवीर चौधरी, कोमल महावर, सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नए ओ.एस.डी. अंजलि राजौरिया ने किया पदभार ग्रहण



ओ.एस.डी. अंजलि राजौरिया ने गंगापुर सिटी में पदभार ग्रहण किया।

गंगापुर सिटी 18 मई। राज्य सरकार ने गंगापुर को जिला घोषित करने के बाद गंगापुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अंजलि राजौरिया को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। विशेष अधिकारी राजौरिया ने गुरुवार को गंगापुर में पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात विशेषाधिकारी द्वारा अधिकारियों से गंगापुर सिटी क्षेत्र के बारे में भौगोलिक एवं प्रशासनिक जानकारी प्राप्त की तथा मिनी सचिवालय परिसर स्थित विभिन्न

राजकीय कार्यालयों का अवलोकन किया। विशेष अधिकारी अंजलि राजौरिया गुरुवार सुबह गंगापुर पहुंची और जहां पर स्थानीय अधीनस्थ अधिकारियों ने विशेष अधिकारी राजौरिया का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इसके बाद पुलिस द्वारा गाई ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजौरिया ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। नए ओएसडी राजौरिया ने मिनी सचिवालय में अपने कार्यालय में एसडीएम नरेंद्र कुमार

मीणा, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला, नगर परिषद आयुक्त पंकज मीणा सहित अन्य अधिकारियों से फीडबैक लिया। इस दौरान विशेष अधिकारी अंजलि राजौरिया ने कहा कि गंगापुर हाल ही नया जिला बना है और नए जिले के हिसाब से यहां पर सफ्टिके हाउस, पुलिस लाइन सहित अन्य कार्यालय बनने हैं, इसके लिए जगह देखकर चिन्हित की जाएगी और जिले के हिसाब से ही पूरा सैटअप तैयार किया जाएगा।

सार-समाचार

जिला कांग्रेस कमेटी कि बैठक आज

करौली (नि.स.)। जिला कांग्रेस कमेटी करौली कि बैठक आज शुक्रवार को दोपहर 12:30 पर सफ्टिके हाउस करौली में आयोजित की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष भूपेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि आज शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी करौली के तत्वाधान में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी के संदर्भ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त संसदीय समन्वयक नटर सिंह एलआरस्कड (लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन) को लागू करेंगे। इसी संदर्भ में आने वाले चुनावों के लिए जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी जिससे विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी तैयारी शुरू कर सके। बैठक में जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठन, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवावल संगठन के अध्यक्ष, विभा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

आवासीय विद्यालय शुरू होगा

करौली (नि.स.) करौली जिले के अन्धपुरा (आननपुरा) में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालय के लिए 23 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस विद्यालय में 6 से 12 तक कक्षाएं संचालित होंगी जिसमें विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 में विज्ञान संकाय में पढाई कर सकेंगे। नवीन पदों में प्रधानाचार्य का एक पद, शाखाता के 6 पद, वरिष्ठ अध्यापक के दो पद, अध्यापक लेवल-द्वितीय के तीन पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-द्वितीय, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय, कनिष्ठ लेखकार, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय व लिपिक ग्रेड-द्वितीय के एक-एक पद, प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला सेवक के तीन-तीन पद शामिल होंगे साथ ही, चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी तथा चौकीदार के कार्य हेतु रेक्सको से भूतपूर्व सैनिक, संविदा अथवा गृह रक्षा स्वयंसेवक या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक की सेवाएं ली जाएंगी।

निरीक्षण किया

डीएम (निस)। ग्राम पंचायत सावई और ग्राम पंचायत ब्राह्मण खेडा में आयोजित महंगाई राहत कैम्प व्यवस्थाओं का कांग्रेसी नेता राजीव सिंह कुम्हरे के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आमजन को महंगाई से राहत लाने के उद्देश्य और सरकार की 10 महात्वाकांक्षी बजट घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन गांव के संग कैम्पों में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टलों पर समस्त पात्र स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान मौके पर कराया।

कार्यालय ग्राम पंचायत, फतेहपुर पंचायत समिति मासलपुर, जिला करौली

क्रमांक:-08 दिनांक: 16.05.2023
ई-निविदा सूचना 01/2023-24

ग्राम पंचायत फतेहपुर, पं.स. मासलपुर की महात्मा गांधी नरगा व ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनागत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए अनुसांगिक सामग्री आपूर्ति हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मों/सप्लायर्स से दिनांक 31.03.2024 तक के लिए दर अनुबन्ध करने के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण <https://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत फतेहपुर
पंचायत समिति मासलपुर,
जिला करौली

सरपंच
ग्राम पंचायत फतेहपुर
पंचायत समिति मासलपुर,
जिला करौली



क्या आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 (अंतिम तिथि 31 मई 2023) के लिए अपनी खाद्य विनिर्माण इकाई की वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी

कैसे विवरणी दाखिल करनी है

- सभी अनुज्ञापितधारक विनिर्माणकर्ता (रिलेबल एवं रि-पैकर सहित)
- आयातक
- दाखिल करने की पद्धतियां
- FoSCoS पोर्टल <https://foscos.fssai.gov.in/> के माध्यम से केवल आनलाईन मोड
- प्रत्येक विनिर्माण/आयात अनुज्ञापितधारि के लिए पृथक विवरणी दाखिल करनी है।
- अस्वीकार्य - भौतिक प्रति अथवा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुति

शास्तियां

- 31 मई 2023 के बाद विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के लिए शास्ति/विवरणी दाखिल करने की तिथि तक विलम्ब के रु. 100 प्रति दिन।
- अधिकतम शास्ति वित्त वर्ष 2021-22 से प्रभावी : वार्षिक अनुज्ञापित शुल्क का 5 गुणा।
- वार्षिक विवरणी दाखिल किये बिना अनुज्ञापित का नवीकरण अनुमत नहीं है।

हेल्पलाइन : कॉल @1800112100 एवं ईमेल : helpdesk-foscos@fssai.gov.in
वार्षिक विवरणी पर अधिक विवरण के लिए FoSCoS पोर्टल पर लाईसेंसिंग/रजिस्ट्रेशन पर FAQs देखें।

कार्यकारी निदेशक (सीएस) एफएसएसएआई

युवक की हत्या के मामले में भूमिया राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया

पुलिस अधीक्षक ने पादरली पहुंचकर मौका मुआयना किया

जालौर/आहोर, (कासं)। आहोर थाना क्षेत्र के पादरली गांव में एक युवक की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को भूमिया राजपूत समाज व ग्रामीणों ने आहोर मोर्चरी के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवर्तन को सुपुर्द किया। उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते पादरली ग्राम पुलिस छावनी में तब्दिल रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्ध ने बुधवार देर रात पादरली पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं गुरुवार को जालौर जिले के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रही।



आहोर थाना क्षेत्र के पादरली गांव में युवक की निर्मम हत्या के विरोध में भूमिया राजपूत समाज व ग्रामीणों ने आहोर मोर्चरी के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया।

जालौर जिले के आहोर उपखंड के पादरली गांव में बुधवार देर रात को सरेआम किशोरसिंह नाम के युवक का धारदार हथियार से कत्ल कर दिया था। घात लगाकर बैठे आरोपी ने सड़क पर जा रहे किशोरी सिंह पर पीछे से वार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी के ऊपर इतना खून सवार था कि सिर को हाथ में लेकर मौका-ए-वारदात से करीब सौ मीटर की दूरी पर डाल दिया। इसके बाद स्वयं पुलिस के समक्ष पेश होकर आत्म समर्पण कर दिया। घटना कर सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आधी रात तक पुलिस मृतक के शव को नहीं उठा पाई। आखिरकार बुधवार देर रात के बाद कांग्रेस नेता उर्मसिंह

चांदराई की समझौदा के बाद शव को आहोर अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। जहां गुरुवार सुबह काफी संख्या में भूमिया राजपूत समाज व पादरली गांव के लोग मोर्चरी के सामने धरना देकर बैठ गए। जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के उग्र होने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करते हुए पादरली गांव एवं आहोर थाने के बाहर व अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।

धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन व पुलिस के समक्ष छह मांगें रखीं और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक शव का

पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पीड़ित पक्ष व ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पीड़ित परिवार को बीपीएल श्रेणी में दर्ज करने, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, मामला फास्ट ट्रैक में चलाने व हत्या के घड़यंत्र में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रशासन व पुलिस ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पीड़ित परिवार को हरसंभव सरकारी मदद देने का आश्वासन दिया।

जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आहोर पहुंचे। जहां जिला कलेक्टर

जैन व कांग्रेस नेता उर्मसिंह चांदराई, एसडीएम शैलेन्द्र सिंह व एएसपी रामेश्वर लाल मेघवाल की समझौदा के बाद परिजन व ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। एएसपी रामेश्वर लाल मेघवाल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवर्तन को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी सांवलाराम भील को हिरासत में लिया है। मामले को शांतिपूर्ण हल करने के लिए डीएसपी रतन देवासी, आहोर थानाधिकारी गिरधर सिंह के अलावा कई पुलिस अधिकारियों व प्रशासनिक अफसरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घटना को लेकर क्षेत्रीय विधायक छगनसिंह राजपुरोहित, पूर्व

बुधवार देर शाम को सरेआम युवक का हथियार से कत्ल कर दिया था

विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, कांग्रेस नेता सवालाराम पटेल, आमसिंह परिहार भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मृतक के शव को परिवर्तन का सुपुर्द किया।

वहीं आहोर पुलिस थाना क्षेत्र के पादरली गांव में एक युवक की निर्मम हत्या को लेकर भूमिया समाज के उग्र विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस ने बुधवार देर रात से डेरा डाल दिया था। जहां पुरे गांव में पुलिस जवान तैनात थे। तथ भील बस्ती में भी पुलिस का विशेष जाजा तैनात रहा है। युवक की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही जालौर पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्ध व जिला कलेक्टर निशांत जैन ने घटना की जानकारी ली। वहीं एएसपी ने गुरुवार सुबह से ही आहोर पुलिस थाने में बैठ कर मामले को स्वयं मोनिटरिंग करती नजर आई। जिला कलेक्टर जैन ने भी आहोर पहुंचकर मृतक के परिवर्तन का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया गया।

हनुमानगढ़ में तेज आंधी से पेड़ गिरे, टीनशेड-छप्पर उड़े

पोल टूटने से रातभर बंद रही बिजली सप्लाई

हनुमानगढ़, (कासं)। देर रात को तेज आंधी के साथ बरसात और ओलावृष्टि हुई। आंधी के कारण कई इलाकों में रातभर बिजली सप्लाई ठप हो गई, जो गुरुवार को कई घंटों बाद बहाल हुई। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए तो कई जगहों पर टीनशेड-छप्पर उड़ गए। जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी में पेड़ टूटकर गिरने से बिजली के 7 पोल टूट गए, जिसके कारण कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई।

कमरे की छत गिरने से एक महिला घायल

बारिश के बीच जंक्शन क्षेत्र में एक मकान में बने कच्चे कमरे की छत गिर गई। इस दौरान मलबे में दबने से एक महिला घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय निवासी गुड्डी देवी ने बताया कि उनके पड़ोस में करीब मूर्ति देवी (45) घर में अकेली रहती है। वह दिहाड़ी-मजदूरी करके गुजर-बसर कर रही है। देर रात को तेज आंधी के दौरान करीब 2 बजे कमरे की छत गिर गई और मूर्ति देवी मलबे के नीचे दब गईं। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर मूर्ति देवी को बाहर निकाला। मलबे के नीचे दबने से मूर्ति देवी के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें लगीं। मलबे में दबने से कमरे में रखा धरतू सामान भी खराब हो गया।

अंधड़ के साथ हुई तेज बारिश

राजस, (निर्स)। अंचल में गुरुवार अल सुबह मौसम ने फिर से पलटी मार ली। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जमकर आंधी चली। इसके बाद झमाझम बारिश का दौर चला। इसके चलते अनेक स्थानों पर पानी भर गया वहीं मौसम में ठण्डापन आने से पंखे कूलर बन्द करने पड़े। गुरुवार दोपहर में फिर गर्मी ने अपना असर दिखा दिया। हालांकि तपन का ज्यादा असर नहीं रहा। गुरुवार देर रात करीब 3 बजे क्षेत्र में जमकर आंधी चली। इससे घरों के बाहर सो रहे लोगों को उठकर अपने घरों में जाना पड़ा। इसके बाद झमाझम बारिश का दौर चला।

सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग, गिरफ्तारियां दी



कानूना में पुलिस को गिरफ्तारियां देते ग्रामीण।

सुजानगढ़, (निर्स)। सुजला जिले की मांग को लेकर कानूना पुलिस चौकी में जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों द्वारा गिरफ्तारियां दी गईं।

जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड रामनारायण रूलाणि, शिक्षक नेता गुरुदेव गोदारा, एडवोकेट बनवारीलाल बिजाराणि, किसान सभा अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, जयदीश सोनी, पवन पारीक, महावीर मूंड, पवन भोज गोदारा बागसर, श्रवणराम, प्रेमराम ठेकेदार, सहाराम मगरसर, धर्मराम

सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमें राजनीतिक पार्टियों को भक्ति छोड़कर जिले के लिए संघर्ष करना चाहिए।

इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष चेताराम कडैला कानूना, रमाकॉट ओमप्रकाश बोडालसर, रामेश्वरलाल, महिपाल भंवरलाल गोदारा मूंडा, बजरंग सिंह फौजी करेअरा, महेंद्र पाल भूराराम ढाका लिखमोसर, केसरा राम गोदारा बागसर, श्रवणराम, प्रेमराम ठेकेदार, सहाराम मगरसर, धर्मराम

जिंजा, राजकुमार शर्मा, ओमप्रकाश साहू, छगन सिंह राजपूत मूंडा, रामनिवास सारण नारायणराम गोदारा, कमल डारा गेडाप, राजेश सारण, ओमप्रकाश ज्योषी आदि के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 750 लोगों ने कानूना पुलिस चौकी पहुंचकर गिरफ्तारियां दीं। वक्ताओं ने आव्हान किया आगामी सभा 4 जून को जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पुराना बस स्टैंड पर होगी, जिसके लिए सभी को न्यौता दिया गया।

बुजुर्ग ने चाकू दिखाकर महिला से रेप की कोशिश की

अनुपगढ़, (कासं)। 58 साल के बुजुर्ग ने चाकू दिखाकर महिला से रेप की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर उस तेजाब फेंक दिया। वह जैसे-तैसे जान बचाकर भागी। वारदात के बाद आरोपी भाग गया। वहीं 8 से 10 फीसदी तक झूलसी महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

महिला पर तेजाब फेंका, 8 से 10 फीसदी तक झूलसी

अनुपगढ़ थानाधिकारी फूलचंद शर्मा ने बताया कि 40 साल की पीड़ित महिला का बयान लिया गया है। महिला ने बताया कि वह कचरा बीनने का काम करती है। उसने दो दिन पहले अपने कमरे से कबाड़ का सामान उठाने के लिए कहा और मोबाइल का नंबर लिया। इसके बाद आरोपी ने रात को भी कबाड़ ले जाने के लिए कॉल किया। महिला ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 4 से 4.30 बजे के बीच सुनार की दुकान पर कचरा बीनने गईं। आरोपी शंकर सदा ने गलत नीयत से उसका

हाथ पकड़ा और चाकू दिखाकर रेप करने की कोशिश की। हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो पास ही रखी तेजाब की बोतल उस पर फेंक दी। जैसे-तैसे हाथ छुड़कर भागी।

महिला ने बताया कि पूरे शरीर में जलन हो रही थी। वह घर पहुंची और अपनी बेटी को साथ लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया। तेजाब के कारण उसका शरीर 8 से 10 फीसदी झूलसा गया। आरोपी भी पीछे आया लेकिन बाद में भाग गया। इसके बाद अनुपगढ़ पुलिस थाने में आरोपी को खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपी किराए का कमरा लेकर अकेला रहता था और बार-बार अपना कमरा बदलता रहता था।

परीक्षा में नकल के लिए दिल्ली से खरीदी थी विग

वीकानेर, (कासं)। नकली बालों की विग में ब्यूटूथ लगाकर राजस्व अधिकारी की परीक्षा देने पहुंचे तीनों आरोपियों को बीकानेर पुलिस दिल्ली लेकर खाना हुई। पुलिस विग विक्रेताओं से पड़ताछ करने के साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालेगी। साथ ही आरोपियों द्वारा ब्यूटूथ लगाने वाले व्यक्ति की तस्वीर भी करवाएगी।

विग में ब्यूटूथ लगाकर राजस्व अधिकारी की परीक्षा देने का मामला

तीनों आरोपियों को बीकानेर पुलिस की सतर्कता के चलते रिवार को आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी (आरओ) भर्ती परीक्षा में नकली बालों में लगे ब्यूटूथ सेटअप के साथ गिरफ्तार किया था। एडिशनल एसपी हरि शंकर ने बताया कि ब्यूटूथ लगाने के मुद्दे नकल सरगना तुमलखाराम कांकर की वल्लाश के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर उसे और उसके सहयोगियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के 12 वीं वाणिज्य व विज्ञान वर्ग का परिणाम जारी

अजमेर, (कासं)। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने सौनिपर सैकण्डरी के वाणिज्य व विज्ञान वर्ग का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणामों में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। बोर्ड परिणाम बोर्ड के नवनिर्वाचित प्रशासक सीआर मीणा ने जारी किया। बोर्ड प्रशासक सीआर मीणा के अनुसार वाणिज्य वर्ग का परिणाम 96.60 प्रतिशत रहा। वहीं विज्ञान वर्ग 95.65 प्रतिशत रहा।

छात्राओं ने मारी बाजी, वाणिज्य वर्ग का परिणाम 96.60 प्रतिशत रहा। वहीं विज्ञान वर्ग 95.65 प्रतिशत रहा

बताया कि इस वर्ष वाणिज्य वर्ग के लिए 29387 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड किए गए थे जिनमें से 29030 ने परीक्षा दी व 28044 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसी तरह विज्ञान वर्ग में 279911 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड किए गए थे जिनमें से 273735 ने परीक्षा दी व 265297 परीक्षार्थी पास हुए हैं।

वाणिज्य वर्ग में छात्राओं का सफलता प्रतिशत 98.01 रहा वहीं 95.85 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण रहे। विज्ञान में छात्राओं की सफलता का

प्रतिशत 97.39 साथ ही छात्रों की सफलता 94.72 प्रतिशत रहा। गत वर्ष के मुकामले विज्ञान और वाणिज्य के परिणाम में गिरावट आई है गत वर्ष के मुकामले दोनों ही विषयों में लगभग एक प्रतिशत परिणाम कम रहा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सौनिपर सैकण्डरी की परीक्षाएँ गत 12 अप्रैल को समाप्त हुई थी इसके बाद बोर्ड प्रशासन परिणाम जारी करने में जुट गया था परीक्षा समाप्ति के 36 दिनों के भीतर ही बोर्ड ने परिणाम जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने कोरोना काल में 29 दिनों में परिणाम जारी था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम पिछले साल की तुलना में एक प्रतिशत

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

टोंक, (निर्स)। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के करीब दो साल पुराने मामले में गुरुवार को पाँक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 45 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी है कि युवक मेहबूब नाबालिग को रात को घर से उठाकर खेत पर ले गया एवं वहां पर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। पीड़िता के दिये बयानों में आरोपी पर बालिका से दो-तीन बार दुष्कर्म किया करने की भी बात सामने आई। कोर्ट में पेश बयानों एवं दस्तावेजों के साथ ही डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया एवं कोर्ट ने सजा सुनाई।

बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज का विरोध

अलवर, (निर्स)। बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अलवर शहर में गुरुवार को मिनी सचिवालय के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मिनी सचिवालय के बाहर गहलोट सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि बिजली फ्री देने का वादा कर सता में आई गहलोट सरकार ने वादाखिलाफी की है। अब बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है जिसके कारण आमजन पर बड़ा भार पड़ा है। इस कारण जनता में आक्रोश है। सरकार को बड़ाए गए फ्यूल

सरचार्ज वापस लेने की जरूरत है। वरना बीजेपी आमजन को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। बीजेपी के नेताओं ने अलवर शहर में पानी का संकट होने का मुद्दा भी उठाया है। शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार आमजन के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने में पूरी तरह फेल है। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, दिनेश भार्गव प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, निर्मल सूरु भाजपा नेता सहित अनेक पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दौहरी पदोन्नति प्रदान करने का आदेश

माध्यमिक शिक्षा चूरा का मामला

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर चलपीट, जोधपुर ने प्राथी दिनेश कुमार मेघवाल द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उसे वर्ष 2010-2011 की रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता एवं उसके पश्चात वर्ष 2018-2019 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति देने का आदेश पारित किया। तहसील सालासर जिला चुरू निवासी दिनेश कुमार मेघवाल की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर 22 दिसंबर 1996 को हुई थी। नियुक्ति के पश्चात वर्ष 2005 में प्राथी ने राजनिधि विज्ञान में स्नाकोतर (एम.ए.) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। प्राथी को योग्यता भी वर्ष 2005 में सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा चुरू द्वारा उसकी सर्विस बुक में इन्ट्राज कर ली गयी। विभाग द्वारा उसकी सर्विस बुक में की गयी इन्ट्राज के पश्चात उसे वरिष्ठता भी उसी अनुरूप प्रदान कर दी गयी। कालांतर में प्राथी से

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर चलपीट, जोधपुर ने आदेश पारित किया

कनिष्ठ कर्मचारियों को वर्ष 2010-2011 की रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। लेकिन प्राथी को वर्ष 2013-2014 की रिक्तियों के विरुद्ध स्कूल व्याख्याता के पद पर राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के तहत पदोन्नति प्रदान की गयी व बाद में वर्ष 2018-2019 की रिक्तियों के विरुद्ध प्राथी से कनिष्ठ स्कूल व्याख्याताओं को पुनः प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गयी। लेकिन विभाग द्वारा प्राथी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी।

अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद विरुद्ध पदोन्नति नहीं देने के स्कूल

व्याख्याता के पद पर देरी से पदोन्नति देने के कारण प्राथी ने कई अप्यावदन प्रस्तुत किये व अंत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भी भेजा मगर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्राथी ने अपने अधिवक्ता प्रमोद बोहरा के माध्यम से एक अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। प्राथी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए अधिकरण ने प्राथी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग को आदेश की पूर्ण पालना तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया।

फ्यूल सरचार्ज वापस लेने की मांग

कोटपुतली, (निर्स)। विधुत विभाग द्वारा बीते कुछ माह से आमजन के बिजली बिलों में वसूले जा रहे फ्यूल सरचार्ज से जहां पहले ही जनता में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी का माहौल था। वहीं दूसरी ओर विगत अप्रैल माह के बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज को 18 से बढ़ाकर 59 पैसे प्रति यूनिट किये जाने से भयंकर आक्रोश व्याप्त है। हाल ही के बिजली बिलों में 250 से लेकर 3000 रुपये तक की राशि बतौर फ्यूल सरचार्ज लोगों के बिलों में जुड़कर आई है। इसी सम्बंध में वरिष्ठ भाजपा नेता शंकर लाल कंसाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को पत्र लिखकर तत्काल बड़े हुए फ्यूल सरचार्ज को वापस लिये जाने की मांग की है। पत्र में कंसाना ने लिखा है कि राज्य सरकार इसके नाम पर प्रदेश की आम जनता से अवैध वसूली कर रही है। राज्य सरकार ने महँगे दामों पर कोयला खरीदा, जिसका खामियाजा प्रदेश को जनता को भुगतान पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 8.5 हजार मेगावॉट क्षमता के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रखरखाव के नाम पर बंद रखकर महँगी बिजली खरीदी। इसका परिणाम अब जनता भुगत रही है।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रैलर पलटा

आग की लपटों में जलता रहा ट्रैलर, कोई जनहानि नहीं हुई

मनोहरपुर, (निर्स)। थाना क्षेत्र के नवलपुरा मोड के पास शेखावाटी होटल के सामने एक ट्रैलर पलट गया जिसमें भीषण आग लग गई।

थाना पुलिस ने बताया कि ट्रैलर में जीरो रोड़ी भारी हुई थी जो दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रैलर असंतुलित होकर व डिवाइडर से टकराकर जयपुर से दिल्ली रोड पर आकर पलट गया, जिससे ट्रैलर में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जिन्होंने ट्रैलर में फंसे सुनील बलाई को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पाकर मौके पर थाना पुलिस मय जापते के पहुंची दमकल कर्मचारियों ने ट्रैलर को आग की बुझाकर आग पर काबू पाया। जिसके बाद क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रैलर को साइड में करवाकर यातायात को खुलवाया गया।

इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि करीब आठ घंटे तक आग की लपटों में ट्रैलर जलता रहा। देखते ही देखते आग ने रफ्तार पकड़ी और धू धू कर



हादसे के बाद उठता धुआं।

ट्रेलर जलने लगा। देर बाद सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचकर आग को

बुझाया गया। इस दौरान करीब आठ घंटे तक हाड़वे पर जाम लगा

रहा जिससे ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डायवर्ट किया गया।



अजमेर में कांग्रेसियों से फीडबैक लेने के लिये राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के आने से पहले ही कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गये। एक गुट ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया इसके अलावा माइक भी बंद करवा दिया। मामला शांत करने के लिए जब आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व रामचंद्र चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो दोनों गुटों के बीच जमकर लात-धुंसे चले। स्थानीय कांग्रेसियों ने बाहर से आये नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को मारपीट कर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया।

अजमेर में पायलट और गहलोत समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई

राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अजमेर शहर के कार्यकर्ताओं का फीड बैक लेने आने वाली थीं, उससे पहले ही मारपीट हो गई

अजमेर, 18 मई, (कांस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान में कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन के अजमेर कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के दो गुटों में भारी भिड़ंत हो गई, और विवाद इतना बढ़ा कि धवन के आने से पहले ही पायलट गुट के कांग्रेसियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों गुटों में जमकर लात-धुंसे चले यहाँ तक कि कार्यक्रम स्थल भी गोविंदम मैरिज गार्डन से बदलकर सर्किट हाउस करना पड़ा।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ व डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, उनके समर्थक व स्थानीय कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया बात बढ़ गई और जमकर मारपीट हुई। स्थानीय कांग्रेसियों ने दूसरे गुट को मारपीट कर कार्यक्रम स्थल से निकाल दिया। चर्चा है कि सीएम अशोक गहलोत की शह पर आर.टी.डी.सी. अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को राजनैतिक व प्रशासनिक दखल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अधिकतर कांग्रेसी नाराज हैं।

अजमेर में कांग्रेस की सचिव व

- शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी व देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आने पर नाराजगी जताई और इसी बात पर विवाद बढ़ गया।
- बाद में धर्मेंद्र राठौड़ भी कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंच गए तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि स्थानीय कांग्रेसी धर्मेंद्र राठौड़ के बढ़ते राजनैतिक व प्रशासनिक दखल से नाराज हैं।

राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन का फीडबैक कार्यक्रम 11 बजे से गोविंदम मैरिज गार्डन में शुरू होना था पर उससे पहले ही मारपीट हो गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अजमेर डेयरी फैडरेशन अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुंच गए, जिससे बात बिगड़ गई। उसके बाद शहर जिला कांग्रेस ने निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया।

विजय जैन का कहना था कि इस फीडबैक कार्यक्रम में केवल पदाधिकारियों को ही भाग लेना है। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भीड़ जमा नहीं की जानी चाहिए और इसी बात को लेकर राम चंद्र चौधरी और विजय जैन

आपस में भिड़ गये। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक माने जाने वाले रामचंद्र चौधरी थे तो दूसरी तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक विजय जैन। मद्द्ता से कांग्रेस विधायक रामेश पारीक, पूर्व विधायक नारायण गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पायलट समर्थक भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना के बाद कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। आर.टी.डी.सी. चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जब नाराज पायलट समर्थकों को मनाने के लिए पहुंचे तो एक बार फिर पायलट समर्थक उग्र हो गए। उन्होंने राठौड़ के साथ आए एक कार्यकर्ता को पिटाई कर दी, भीड़ के बीच में से पुलिस ने धर्मेंद्र राठौड़ को बाहर निकाला।

निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि अजमेर शहर के पदाधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन वह डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी अपने डेयरी संचालकों के साथ वहां आ गए जिससे बात इतनी बिगड़ गई।

सूत्रों ने बताया कि, आज एआईसीसी की सचिव राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और फीडबैक लेने के लिए अजमेर के गोविंदम मैरिज गार्डन में सुबह 11 बजे पहुंचना था, इससे पहले ही कांग्रेस देहात के पदाधिकारी और अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी अपने समर्थकों के साथ अमृता धवन का स्वागत करने के लिए वहां पहुंच गये। कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने देहात के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने की बात कही, इसे लेकर देहात और शहर के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए और देहात के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने के लिए इंकार कर दिया। इसके बाद शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए और उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और साउण्ड सिस्टम भी हटा दिया।

घड़साना मंडी में 60 भेड़ और पांच बकरियों की मौत

अनूपगढ़, 18 मई (कांस)। घड़साना मंडी के गांव 2 आर.के.एम. (कुंडल) में बुधवार देर रात को संदिग्ध परिस्थितियों में 60 भेड़ और 5 बकरियों की मौत हो गई। पशुपालक शौकत अली ने इसकी सूचना आज सुबह सरपंच महावीर बिरट को दी। सूचना मिलने पर सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया।

सरपंच ने बताया कि इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है मगर अभी तक भेड़ और बकरियों की मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। सरपंच ने बताया कि, मृत पशुओं में से लगभग 10 पशुओं के चोट के निशान भी हैं। माना जा रहा है कि, आसमान से बिजली गिरने से भेड़ और बकरियों की मौत हुई है।

सरपंच महावीर बिरट ने बताया कि, उन्हें पशुपालक शौकत अली ने जानकारी दी कि, देर रात्रि जब तेज बरसात हो रही थी तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में सो रहा था और बाहर बाड़े में भेड़ और

■ भेड़ और बकरियों की मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। सरपंच ने बताया कि, मृत पशुओं में से लगभग 10 पशुओं के चोट के निशान भी पाए गए हैं।

बकरियां बंधी हुई थीं। शौकत ने बताया कि, सुबह लगभग 3-4 बजे जब वह लघुशंका के लिए उठा तो उसने देखा कि, बाड़े में सभी भेड़ें और बकरियां मृत पड़ी हुई हैं।

सूचना मिलने पर सरपंच महावीर बिरट, जिला परिषद सदस्य दलीप मेघवाल, राजू जाट, विक्रम ठाकुर सहित अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। सरपंच ने इसकी सूचना तहसीलदार को दे दी है मगर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। सरपंच ने बताया कि, पशुपालक शौकत अली पशुओं के जरिए ही अपना जीवन यापन कर रहा था, अब उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई भी सहारा नहीं है। सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है।

तहसीलदार ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलने पर डॉक्टर को टीम भी मौके पर भेजी जा रही है और वह खुद भी मौके पर जा रहे हैं।

‘वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण कैसे हो रहा है?’

अदालत ने जलदाय विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं

जयपुर, 18 मई (कांस)। राजस्थान हाई कोर्ट ने वन विभाग की भूमि पर जलदाय विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पानी की टंकी बनाने के विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई की और अदालत ने जलदाय विभाग के सचिव, वन विभाग के संरक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शुक्रवार को पेश होने के आदेश दिए। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश अनिल कुमार उपमान ने मंगल कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।

■ मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि, जलदाय विभाग ने “नाहरगढ़ नोटिफाईड एरिया” में बड़ी टंकी के निर्माण कार्य को अनुमोदित कर दिया, जबकि उसने वन विभाग से अनुमति ही नहीं ली है।

■ याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि, जलदाय विभाग के अनाधिकृत निर्माण की आड़ में कई अन्य स्थानीय लोगों ने नाहरगढ़ की पहाड़ी पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं और “सिंकिंग एरिया” होने के कारण भी यह खतरनाक है।

कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया है कि जलदाय विभाग के द्वारा अनुमोदित इस अवैध निर्माण की आड़ में कई अन्य स्थानीय लोग भी उक्त क्षेत्र में निर्माण कार्य करने लगे हैं और उन्हें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.) द्वारा अनाधिकृत तरीके से बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने इन अवैध निर्माणों और अनाधिकृत तरीके से बिजली कनेक्शन के बांटे जाने के खिलाफ भी कार्यवाही की गुहार लगाई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले पर अदालत ने जलदाय विभाग और वन विभाग से जवाब मांगा था, परंतु

अभी तक भी दोनों विभागों की ओर से कोई जवाब दायर नहीं किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने शुक्रवार को विभागों के अधिकारियों को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है।

तेज आंधी से जन जीवन अस्त-व्यस्त

बीदासर, 18 मई (निर्स)। कस्बे में बुधवार को आधी रात के बाद तेज अंधड़ आया। लगभग दो घण्टे तक चली इस तेज आंधी से कस्बे की विद्युत व्यवस्था चरमका गई। कई जगह पेड़ व बिजली के पोल टूटकर जमीन पर आ गिरे। वहीं घरों में घूल ही घूल हो गई, जिससे गृहणियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंधड़ ने बिजली के कई पोल गिरा दिए जिसके

■ चूक के बीदासर कस्बे में तेज अंधड़ से पेड़ व बिजली के 12 खम्बे टूट गए, विद्युत विभाग को भारी नुकसान हुआ है।

कारण कस्बे सहित आसपास के गांवों की बिजली गुल रही।

जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता राजेश कुमार मीणा ने बताया कि, बुधवार की देर रात आये तेज अंधड़ से क्षेत्र में 12 विद्युत पोल तथा दो डीपी टूट कर जमीन पर आ गिरीं। इससे पूर्व, दो दिन पहले आये अंधड़ में भी क्षेत्र में 150 विद्युत पोल टूटकर चकनाचूर हो गये थे, जिससे विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली, 18 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टै आर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। यानि कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जातीय जनगणना पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार किया जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने दो टुक कहा, पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आगे बाँर इस पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को इसमें अंतरिम राहत नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट अपनी दी तारीख 3 जुलाई पर सुनवाई कर फैसला नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को यहाँ दलील सुनेगा।

केन्द्र सरकार प्राइवेट सैक्टर के लोगों को निदेशक व उप सचिव के पदों पर नियुक्ति देगी

केन्द्र सरकार ने 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने का फैसला किया है

नई दिल्ली, 18 मई। केंद्र सरकार अपने कुछ विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा बड़ी अभियान है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) से ऐसे विशेषज्ञों को

- आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और ग्रुप 'ए' सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।
- बयान में कहा गया है कि, उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

‘लेटरल एंट्री’ यानी सरकारी विभागों में प्राइवेट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। आमतौर पर, संयुक्त सचिवों,

किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नागरिक उद्युगन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और भारी उद्योग मंत्रालय के लिये की जाएगी।

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बयान के मुताबिक, इन मंत्रालयों/विभागों में ‘लेटरल एंट्री’ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को शामिल किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बंगाल में “द केरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं है।

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा, “फिल्म देश में हर जगह चल रही है। आप पूरे राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते।”

शेष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं उठाने और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने फिल्म निमाता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्के का एक बयान भी दर्ज किया कि किसी भी विवाद को शांत करने के लिए 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में एक डिस्कलेमर डाला जाएगा कि 32,000 रूपांतरण के कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं और फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है।

बैंच ने फिल्म द केरला स्टोरी देखने

का भी फैसला किया, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या स्वीकार्य है या नहीं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के बाद मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के फैसले से उल्टव याचिकाओं पर विचार करेगी। इन उच्च न्यायालयों ने उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।

जल्लीकट्टू व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार द्वारा पारित कानून में जानवरों के प्रति क्रूरता (यदि कोई हो) का ध्यान रखा गया है।

न्यायमूर्ति बोस ने फैसले का एक हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि किसी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा क्या है, इस पर निर्णय लेने के लिए विधायिका सबसे अच्छी संस्था है और इसे न्यायपालिका द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।

छवि परिवर्तन कार्यक्रम के तहत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। रिजोजू ने अपने मंत्रालय की ओर से एक नोट पोस्ट किया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा सभी जजों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया है।

भारत को नये विधि मंत्री ऐसे अजीबोगरीब समय पर मिले हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय तथा सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर प्रायः मतैक्य नहीं रहा।

रिजोजू का संक्षिप्त कार्यकाल बड़ा विवादालय रहा क्योंकि सरकार और न्याय पालिका के बीच प्रारंभिक स्थिति बनी रही तथा जजों की नियुक्ति की कोलीजियम व्यवस्था को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की खुली आलोचना की गई।

फरवरी में, सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की एक बैंच ने जजों की नियुक्तियों और तबादलों को मंजूरी दिये जाने में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। बैंच ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया

तथा एक ऐसी “प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही की चेतावनी दी थी, जो संभवतः रूचिकर नहीं हो।”

रिजोजू ने इस चेतावनी को उपेक्षा कर दी थी तथा कह दिया था कि देश का शासन संविधान तथा जन आकांक्षाओं के अनुसार चलेगा। उन्होंने एक समारोह में कहा था, “कभी-कभी कुछ मुद्दों पर देश में चर्चाएं हुआ करती हैं तथा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कुछ भी कहने से पहले यह सोचना होता है कि ऐसा कहना देश हित में होगा या नहीं।” उन्होंने जोर देते हुये कहा था कि “कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चेतावनी नहीं दे सकता।”

सरकार बयान न्याय पालिका टकराव उस समय और बढ़ गया था, जब रिजोजू ने गत वर्ष कह दिया था कि कोलीजियम व्यवस्था संविधान के लिये “परायी” है तथा उसे जन-समर्थन हासिल नहीं है। उन्होंने जहाँ,

“आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि संविधान के साथ किसी असम्बद्ध निर्णय को केवल इसलिये देश का समर्थन मिल जायेगा कि वह निजिय अदालत या कुछ जजों द्वारा लिया गया है।”

उन्होंने संसद द्वारा 2014 में पारित किये गये नैशनल जुडिशियल अपॉइन्टमेंट्स कमीशन (एन.जे.ए.सी.) एकट का भी उल्लेख किया था, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों के मामले में सरकार को बड़ी एवं निर्णायक भूमिका प्रदान कर दी गई थी, तथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

जहां विधि राज्य मंत्री बघेल को दूसरे मंत्रालय में भेजे जाने के पीछे इस प्रथा का हवाला दिया जा रहा है कि जिस मंत्रालय का मुखिया स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री हो, उसमें कोई सहायक मंत्री नहीं हो सकता, वहीं असली तथ्य यह है कि उन्होंने 8 मई को उस समय एक विवाद को जन्म दे दिया था, जब उन्होंने दावा किया था कि

सहिष्णु मुस्लिम नगण्य संख्या में हैं, तथा सहिष्णु नजर आने वाले लोग भी सहिष्णुता को एक मुखौटे के रूप में काम में लेते हैं ताकि वे सार्वजनिक जीवन में बने रहें तथा राज्यपाल एवं उपरप्रतिपति बन सकें।

सूत्रों का कहना है कि बघेल की यह मान्यता और उसे व्यक्त करने का समय भाजपा हाई कमान के गले नहीं उतरा था क्योंकि अब तो आर.एस.एस. भी मुस्लिमों के रिश्ते सुधारने के प्रयास कर रही है। इसके अलावा, सरकार के स्तर पर यह भी महसूस किया जा रहा है कि सरकार को तनाव कम करने की जरूरत है जो कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान उस समय पैदा हो गई थी, जब यह मानकर साम्प्रदायिक मुद्दे उठाये गये थे कि ऐसा करने से बड़ा चुनावी फायदा मिलने में मदद मिलेगी।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री तथा उनकी सरकार को एक नये रूप में प्रस्तुत करने की कवायद को तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है।

ग्रेनाइट की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

थानाधिकारी ने बताया कि, मृतक अशोक, पुत्र मदन लाल मीणा, नरडी थाना सांवर, महज दो दिन पूर्व ही ग्रेनाइट खदान पर मजदूरी के लिए आया था। गुरुवार को, काटकर चढ़े हुए ग्रेनाइट के ब्लॉक्स के ढेर से ब्लॉक हटाने के लिए मृतक अशोक फोकलेटण्ड मशीन से कार्य कर रहा था।

इसी दौरान चट्टान ब्लॉक का बड़ा भाग फोकलेटण्ड मशीन की केबिन पर आ गिरा, जिससे केबिन में बैठे श्रमिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलने के बाद ग्रेनाइट खानाद के संचालक ने मौके पर पहुंचने के बजाय अपने प्रतिनिधि को भेजकर शव का अंतिम संस्कार करवाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिवार 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुद्दीयार के पास बैठ गये। दोनों पक्षों के बीच तकरौबन चार घंटे तक चली समझाइश व सहमति वार्ता में आर्थिक सहायता राशि को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

ममता बनर्जी “पटाखा फैक्टरी” में बम

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुभव की बात है कि इस प्रकार के अस्थायी ठिकानों में बने हस्तनिर्मित बमों का इस्तेमाल राजनैतिक हिंसा के लिये किया जाता है।

पुलिस का शक है कि तथाकथित पटाखा फैक्ट्री में इसी प्रकार के कोई क्रियाकलाप चल रहा था तथा कुछ चिनगारियाँ निकलने से इतने जबरदस्त विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। इस ब्लास्ट में कम से कम दस लोग मारे गये तथा बीस लोग घायल हो गये, जिनमें से कुछ जीवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस तथाकथित पटाखा फैक्ट्री का मालिक स्थानीय पंचायत का तुणमूल प्रमुख था। ग्रामीण लोगों ने इस पटाखा फैक्ट्री के अवैध संचालन की शिकायत भी की थी तथा ऐसा संदेह था कि व्यवस्था इन अपरिष्कृत हस्तनिर्मित बमों को बनाने के लिये ढाल का काम कर रही थी।

इस संदेह देखने में इसलिये और भी ज्यादा विवचनीय प्रतीत होता है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं तथा सत्तारूढ़ दल वोटों पर कब्जा करने एवं

पंचायत बोर्डों में जीत के लिये ऐसे बमों एवं हिंसा के मदद से दबाव बनाने तथा जोर-जबरदस्ती करने का बीजतम खेल खेल सकता था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी अवैध फैक्ट्रीयों केवल दण्डाभाव की स्थिति में ही नहीं चल सकतीं, इनके संचालन के लिये सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रदत्त राजनैतिक संरक्षण भी जरूरी है। एक ऐसे राज्य में, जहाँ सत्तारूढ़ तुणमूल कांग्रेस की सहमति के बिना न तो एक ईंट लगाई जा सकती है और न हटाई जा सकती है, वहाँ इतने बड़े जोखिम वाली फैक्ट्रीयों का सतत संचालन सत्तारूढ़ पार्टी की अनकही/मौन स्वीकृति से ही संभव हो सकता है। इस विस्फोट की गिरफ्तारी से बचने के लिये भ्रमकर ऑडिश चला गया बताते हैं। इस स्थिति को भी एक प्रकार गलत चीज माना जा रहा है जो स्थानीय पुलिस तथा राजनैतिक पार्टी के स्तर की मौन अनुमति के चलते ही हो सकती है।

विस्फोट के समाचार की जानकारी मिलते ही, राज्य के विपक्षी दलों ने इस मामले की एन.आई.ए. द्वारा जांच कराये जाने की माँग शुरू कर दी थी। राज्य पुलिस पर लोगों का ऐसा भरोसा नहीं है कि वह कोई भी काम “प्रोफेशनली” करती है। जहाँ ममता बनर्जी इस बात का जबरदस्त विरोध करती कि बंगाल की किसी स्थानीय घटना की जाँच कोई केन्द्रीय एजेंसी करे, लेकिन इस मामले में, बनर्जी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुये, एन.आई.ए. जाँच की माँग के प्रति सहमति व्यक्त की है कि विस्फोट बहुत बड़ा और भयानक था तथा इसमें इतने ज्यादा लोग मरे हैं। इसके अलावा, स्थानीय गाँव में स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सका है। घटना के शीघ्र बाद ही, पार्टी को जो टीम वहाँ गई थी, उसे स्थानीय ग्रामीणों ने यह कहकर लौटा दिया था कि ऐसी घटनाएँ सत्तारूढ़ पार्टी के आक्रामक नेताओं की ढील एवं सक्रिय लिप्तता के फलस्वरूप ही हो सकती हैं।

MARUTI SUZUKI

NEXA

AN SUV MADE TO MATCH YOUR STRIDE.

PRESENTING
FRONX
THE SHAPE OF NEW



Scan to know more about FRONX

CREATE. INSPIRE.



1.0L Turbo Boosterjet Engine with Progressive Smart Hybrid



360 View Camera



Head Up Display



NEXTre' Rear Combination Lights



In-Built Suzuki Connect



Wireless Charger

VISIT YOUR NEAREST NEXA DEALERSHIP OR LOG ON TO WWW.NEXAEXPERIENCE.COM TO BOOK YOUR TEST DRIVE.

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-NEXA

www.nexaexperience.com
NOW YOU CAN ALSO BOOK ONLINE

CONTACT YOUR NEAREST NEXA DEALER: ALWAR: NEXA MANHAR VILLA (FORTUNE CARS PH: 7230029424), BHIWADI: NEXA BHIWADI CENTRAL (FORTUNE CARS PH: 9214794313).

Accessories and features shown may not be part of standard equipment. Black glass on the vehicle is due to lighting effect. Images used are for illustration purposes only.